DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6256 on the 14th April, 1969 regarding opening of C.G.H.S. Dispensary in Naraina Residential Scheme area very soon;

(a) whether it is a fact that the area is fast developing and the number of families of Government employees are likely to exceed 2,000 in the area very soon;

(b) if so, whether Government propose to conduct a survey and open a separate dispensary in the area;

(c) if so, by when; and

(d) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) No basis has been mentioned for the assumption that the number of Government employees in this area will exceed 2000 very soon.

(b) Not at present.

(c) Does not arise.

(d) New dispensaries in areas which qualify will be opened when funds are available.

11.17 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ARRANGEMENT FOR TAKE OVER BY GOVERNMENT OF TIMES OF INDIA GROUP OF PAPERS

MR. SPEAKER: We shall take up the next item.

SHRI NAVAL KISHORE SHARMA (Dausa): On a point of submission, with regard to the next item on the agenda, the call attention notice. I want to submit that the call attention notice involves certain important legal and moral issues. It should not be disposed of in this manner. Therefore, would you kindly allow a discussion on this subject, at least half an hour discussion?

MR. SPEAKER: Let the Minister make his statement. Shri S. M. Joshi.

श्री एस० एम० जोशी : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नलिखित विषय की ओर औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा कम्पनी-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

> "श्री शान्ति प्रसाद जैन तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कुप्रबन्ध तथा गबन के मामलों में आगे कार्यवाही न करने का आश्वासन दे कर सरकार द्वारा टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप के पत्र-पत्रिकाओं को निकट भविष्य में वस्तुतः अपने हाथ में ले लिये जाने की कथित व्यवस्था।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEPARTMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDY): The following matters pending in the Bombay High Court are connected with Messrs. Bennett Coleman & Co. Ltd., publishers of the Times of India Group of Papers.

(1) Petition under Section 398 of the Companies Act 1956.

(2) Petition under Section 388B of the Companies Act, 1956.

(3) Civil Suit filed by Messrs. Bennett Coleman & Co. Ltd. for the recovery of about Rs. 36 lakhs from Shri S. P. Jain and other persons in respect of the amounts stated to have been misappropriated by him or for his benefit with interest thereon.

(4) Appeal by the company against the injunction granted by the erstwhile Companies Tribunal against the order of suspension of five senior employees of the compnay.

[Shri Raghunath Reddy.]

(5) Petition by two Government directors against the with-holding of pensionary benefits of one of the senior employees of the company.

(6) Appeal by the company against the objection of the Company Law Board under section 635B to the proposal for the dismissal of five senior employees.

The other pending matters are—

(i) Writ appeal before a Division Bench of the Calcutta High Court filed by Shri S. P. Jain and Shri A. P. Jain challenging the valadity of the action proposed under section 388B of the Companies Act, 1956.

(ii) Charge-sheet filed by the Special Police Establishment against Shri S. P. Jain and others for offences under Sections 120B/409/109 and 409 of the Indian Penal Code before the Additional Chief Presidency Magistrate, Bombay.

The proceedings relating to he petition under section 388B of the Companies Act have been stayed by the orders of the Calcutta High Court at the instance of the respondents. The proceedings under section 398 of the Act are going on from day-to-day in the Bombay High Court. Certain proposals were received on behalf of the main respondents regarding the reorganisation of the Board of Directors of Messrs. Bennett Coleman & Co. Ltd. These matters connected with the reorganisation of the Board, the period of life of the reorganised Board and of protection of the employees who have assisted in the investigations have been considered by the Government for making appropriate submissions to the Court. In Government's view the re-organised Board should have a majority of non-shareholder Directors for a reasonable period in the interests of the Company and the employees concerned should be protected.

It is quite incorrect to speak of virtual take-over of The Times of India Group of Newspapers by the Government in return for not proceeding with cases of mismanagement and misappropriation against Shri Shanti Prasad Jain and others. The fact that the petition under Section 399B of the Companies Act is continuing and that a criminal prosecution has been filed, will itself show that action has been, and is being, taken purely on merits.

श्री एस० एम० जोशी : यह मामला बहुत पुराना है और गम्भीर भी है । 1964 में इस कम्पनी के खिलाफ यह मामला कोर्ट में गया था और कम्पनी एक्ट की धारा 398 और 388 बी के मातहत यह काम चला । इसके दो तीन कारण हैं । एक तो गबन वगैरह हुआ है । मसलन रद्दी जो टाइम्स आफ इंडिया में थी उसको बेचा गया और जो पैसा वसूल हुआ कम्पनी के लोगों ने बिना हिसाब किताब बताये उसे अपने पास जमा कर लिया । ऐसी चीज उस में थी । उनको ले कर कोर्ट का 398 के मातहत जो आर्डर होना था वह हो गया । बोर्ड बना हुआ है जिस में कम्पनी की मैजारिटी है । दो गवर्नमेंट की तरफ से उस में है और हाई कोर्ट की तरफ से चेयरमैन नियुक्त किया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि मामले को कोर्ट में ले जाने का सरकार का मकसद क्या था ? दो चीजें उस में मैं देखता हूं । एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना आवश्यक था और इसको ले कर हकूमत वहां कोर्ट में गई । दूसरे कम्पनी और उस में जो कर्मचारी हैं उनके हितों को देखना था । साथ ही यह जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको देश के हित में रोकना था । दो तीन मकसद ही हो सकते थे । जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, मैं देखता हूं कि इस कम्पनी के द्वारा कर्मचारियों के

साथ अन्याय ही हो रहा है, अन्याय ज्यों का त्यों चल रहा है । लाक आउट भी हुए हैं । साथ ही वेज बोर्ड का जो फैसला आया था उस पर भी अमल नहीं किया गया । इसके साथ-साथ भ्रष्टाचार का सवाल भी है ।

जो जवाब दिया गया है उससे सब मामला साफ नहीं हुआ है । 388 बी जो है उस में यह बताया गया है कि कोई डायरेक्टर या कोई व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में आरोपित हो, उसको डायरेक्टर नहीं बनना चाहिये । अभी जो डायरेक्टर बनाये जा रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला है कि कोर्ट में सरकारी वकील द्वारा यह कहा गया है कि हम इस चीज के लिए राजी हैं कि ये जो डायरेक्टर कम्पनी की तरफ से रहेंगे उसे में जिन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये हैं वे भी रहें । जब कोर्ट में यह आया तो सरकारी वकील ने इसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शित नहीं किया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं होनी चाहिये. यदि होनी चाहिये तो उसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है ? जैसे आपके जो चार डायरेक्टर वहां जायेंगे उस में क्या मजदूरों के प्रतिनिधि भी जा सकते हैं ? वरना उनके हितों की रक्षा कैसे होगी ?

जब फैसला हो जाएगा तो उसका मतलब क्या यह होगा कि 398 के अन्दर जो केस चल रहा है वह खत्म हो जाएगा ? 388 बी के बारे में हाई कोर्ट के द्वारा उनको इजैक्शन मिला हुआ है, उसका क्या होगा ? इस तरह से समझौता कर लेने से क्या क्रिमिनल प्रासीक्यूशन जो है वह कमजोर पड़ता है या नहीं ?

इन सब चीजों के ऊपर पहले जो एटर्नी जनरल थे उनकी राय इन लोगों ने ली थी । राज्य सभा में मंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि उनकी राय हमारे पास आ गई है लेकिन हम लोग उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और जब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक हम उस राय को सभा पटल पर नहीं रख सकते हैं । उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया है । अब क्या हकूमत तैयार है कि एटर्नी जनरल से जो राय मिली थी, उसको सभा पटल पर रखा जाए । सिविल सूट और क्रिमिनल सूट के बारे में पहले के एटर्नी जनरल की जो राय थी क्या उसको सरकार सभा पटल पर रखने के लिए तैयार है ? अभी जो नए एटर्नी जनरल आए हैं क्या उनकी भी राय ली गई है और अगर ली गई है तो क्या उस राय को भी सभा पटल पर रखने के लिये आप तैयार हैं ?

यह मुझे पता चला है कि कोर्ट द्वारा जो अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है ? अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो क्या इसकी हकूमत को जानकारी है और अगर है तो किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, यह भी बताया जाए ।

SHRI RAGHUNATH REDDY: Several questions have been raised by the hon. Member. Sir, I hope you would permit me to preface my answer by saying that the entire matter connected with this question is pending before the court and, therefore, is in the nature of *sub judice*. Keeping this in mind, I hope the hon. Members would kindly appreciate that the answers that I may have to give will have to suffer from this limitation that since these matters are pending before the court, we cannot go deep into the question, on the merits of the matter, one way or the other.

SHRI SHEO NARAIN (Basti): On a point of order, Sir. This Government has given an assurance in this House that they will give us the Attorney-General's report. That is

[Shri Sheo Narain]

not before the court. That is a very genuine demand and they must give the report to the House. This is the demand of the full House.

MR. SPEAKER: He has raised only two points: whether there will be any representative of labour on it and whether the new Attorney General has been consulted or not. I do not think that can be *sub judice*.

श्री एस० एम० जोशी : मैंने यह भी पूछा है कि क्या कोर्ट के सामने सरकारी वकील के द्वारा यह कुबूल किया गया है या नहीं कि जो नया बोर्ड बनेगा, उस में उन लोगों के रहने में कोई मुश्किल नहीं है, जिन पर अभियोग लगाया गया है ।

MR. SPEAKER: That comes to the same thing.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The questions raised by the hon. Member are about petitions under sections 388B and 398 of the Companies Act. As far as the petition under section 388B is concerned, as I have already made a submission, the matter is pending before the Calcutta High Court by way of a writ petition filed by the respondent, dismissed by the single Judge, now pending before the Division Bench by way of an appeal filed by the respondents and stay order having been issued by the Division Bench. But as far as that is concerned, that has nothing to do with any kind of negotiations or settlement in relation to proceedings under section 398. The proceedings under section 388B would continue as it has nothing to do with any kind of talks about settlement or with any discussion; that would be in relation to proceedings under section 398. I would like to make that submission very clear.

As far as the criminal proceedings that are now proceeding are concerned, they have nothing to do with proceedings under section 398 pending before the Bombay High Court. The CBI is in charge of the prosecution of the criminal proceedings and they would take their own course as advised by the legal advisers of the CBI.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): Take some energetic steps.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The only question that we are now concerned with is in relation to proceedings under section 398 and it would stand to reason—it would be my submission—that where a petition has been filed for removal of the respondents under section 398 for misfeasance or malpractices, certainly such of the persons who are so mentioned in the petition cannot be the directors; they cannot continue in any kind of positions. If any settlement is likely to take place, certainly it would exclude such persons mentioned as respondents in the petition.

The only question that would then arise is whether to continue the proceedings until all the evidence is over—the defence evidence is also over—and leave it to the court to give a decision on merits. Since the object of the proceedings under section 398 is to get a proper management of the company, if that can be achieved even otherwise, by putting an end to the court proceedings and thereby saving some money for the Government also . . . (*Interruption*)

SHRI S. M. JOSHI: How much have you spent by now?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: If such a settlement would be helpful and if it would be in the interest of the company, the public and the persons who are employed, Government may consider it favourably and the lawyers would take the appropriate action.

SHRI RANGA (Sri Kakulam) Has the Chairman resigned?

SHRI SHEO NARAIN: Sir, he is a progressive minister. We put a definite question but he is not ready to give us the Attorney-General's report. What is this? Is this the way to run the Government? We know, you are very progressive. An assurance had been given. You give us the report of Attorney-General. We want it. He must give it.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: May I, with your permission, Sir, state that the hon. Member, Shri Sheo Narain, may kindly pardon my lapse in not directly answering the question relating to the opinion expressed by the former attorney-General? The Government need not have much hesitation to place the opinion of the former Attorney-General on the Table of the House..

SHRI MADHU LIMAYE (Monghyr) Why?

SHRI SHEO NARAIN: What is the objection? You have given an assurance to this House.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I would only like you to appreciate that, in the process of consultation between the Government as a client and the Attorney-General as a legal adviser, several opinions would be expressed from time to time and opinions may differ. But whether it would be correct to place the opinion of the Attorney-General on the Table of the House . . .

SOME HON. MEMBERS: Why not?

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Why not? Because it does not suit you?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I am in your hands, Sir. If you direct me, I am prepared to do so.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: You must direct him, Sir.

SHRI SHEO NARAIN: An assurance was given in the House.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the other question, whether we have consulted the new Attorney-General, I do not think the matter was again referred to the new Attorney-General because already the former Attorney-General had expressed an opinion on the subject.

SHRI RANGA: Sir, I had raised a point and it was also raised by the Hon. Member, Mr. S. M. Joshi. I do not know why he has been trying not to give an answer to that. I want to know whether it is a fact that the Chairman has resigned; whether the Government have come to know about it. He has not given any information about that. About the opinion of the Attorney-General, I would like, if necessary, you to take sometime, also study the matter and give your ruling, not only the former Attorney-General but also the present Attorney-General, as to what are their advices to the Government of India.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: If I have correctly understood Prof. Ranga, the question is, whether the Chairman of Bennet Coleman & Co. has resigned. As far as I am concerned, I have no knowledge about it.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : कुछ दिनों से दिल्ली में, और बाहर भी, यह हवा बड़ी गर्म है कि यह सरकार समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का अपहरण करना चाहती है। (व्यवधान) यह निर्णय उसी दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है । यदि किसी दिन यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया गया, तो समाचारपत्र भी आल-इंडिया रेडियो की तरह से भाटों के गीत बन कर रह जायेंगे और वह देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की सूचना होगी ।

अगर श्री शन्ति प्रसाद जैन या उन के दूसरे सम्बन्धी बिल्कुल निर्दोष हैं, तब तो सरकार इस संगठन के सम्बन्ध में बातचीत के माध्यम से जो कोई मार्ग निकालना चाहती है, उस की क्या आवश्यकता है ? और अगर वे दोषी हैं, तो उन के साथ समझौते की बातचीत विचाराधीन क्यों है ? ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हैं । मैं माननीय मंत्री से दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो कोर्ट के निर्णय को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

मेरा पहला सीधा-सादा प्रश्न यह है कि यह जो समझौता हो रहा है, क्या इस में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं, जिन का जनहित निधि से सीधा सम्बन्ध है । जनहित निधि नामक ट्रस्ट द्वारा लखनऊ से **नैशनल हैरल्ड** आदि तीन अखबार और यहां से **नेशनल हैरल्ड** पत्र निकाले जाते हैं । श्री शान्ति प्रसाद जैन की ओर से इस ट्रस्ट को पच्चीस लाख रुपया दिया गया है । इस ट्रस्ट में कैबिनेट के एक मिनिस्टर श्री के० के० शाह, और राज्य सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं । उन के माध्यम से बातचीत में यह तय हुआ है कि यद्यपि कोर्ट ने यह निर्णय किया है कि जैन परिवार के दो सदस्य बोर्ड में रहेंगे, लेकिन उन को बढ़ा कर तीन सदस्य कर दिये जायें और गवर्नमेंट के भी तीन सदस्य बोर्ड में रहेंगे । क्या यह सही है कि गवर्नमेंट की ओर से जो तीन सदस्य रहने वाले हैं, उन के सम्बन्ध में श्री शान्ति प्रसाद जैन से परामर्श लिया गया है और गवर्नमेंट द्वारा नामीनेट किये जाने वाले उन सदस्यों में से एक तो मोदीनगर के एक बहुत बड़े उद्योग-पति हैं और दूसरे मद्रास के भूतपूर्व एड-वोकेट ज नरल, श्री मोहन कुमारमंगलम हैं, जो इस समय इंडियन एयरलाइन्ज के चेयर-मैन हैं ?

मैं यह भी जा ना चाहता हूं कि पीछे 20 तारीख को केबिनेट कोलमन के सम्बन्ध में कैबिनेट में क्या निर्णय लिया गया है । किस सूचना के बताने से कोर्ट का निर्णय प्रभावित हो, मंत्री महोदय भले ही वह सूचना न दें, लेकिन वह इस सम्बन्ध में कैबिनेट के 20 तारीख के निर्णय को बताने से क्यों हिचकते हैं ?

श्री शान्ति प्रसाद जैन के साथ ही इस संगठन के जो और बड़े अधिकारी दोषी हैं उन के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: Under section 398 of the Companies Act, when a petition is filed seeking to disqualify the respondents in view of charges of misdemeanour committed by them, naturally the petitioner would request the court that they should not be included for the purpose of any responsibility. Since the charges against Mr. Shanti Prasad Jain and others were connected with this, it was the petition of the Government that for the purpose of administration in the interest of public and in the interest of the company, representatives of non-share-holders must be placed on the Board of Directors so that, having regard to the previous history, the company might be managed in public interest and also in the interest of the company. I am again submitting to the hon. House that this can only be a submission made to the court by the petitioner and that the decision lies squarely with the court; the court's orders are final in this respect, whatever may be the arguments advanced by the Government in this respect. The court has a duty to pass an order; notwithstanding any argument or submission made by the Government or the other side, the court has ample powers to pass an order in public interest, and there is sufficient case law on the subject.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल तो बड़े साफ थे, आप ने सुने होंगे । मैं समझता हूं कि मेरे प्रश्नों को अगर मंत्री महोदय न समझ सके हों तो आप कृपा कर के उन को समझाएं । मेरा एक प्रश्न यह था कि जनहित निधि ट्रस्ट को 25 लाख रुपया क्या उन्होंने दिया और जनहित निधि ट्रस्ट के माध्यम से क्या आपस में यह समझौता हुआ ? दूसरा प्रश्न यह था कि 20 तारीख को कबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय हुआ वह क्या है और तीसरा यह था कि जो उन के साथ बड़े अधिकारी दोषी हैं उन के

ऊपर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? मैं चाहता हूं कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आए । दूसरे यह कि के० एन० मोदी और कुमार मंगलम के संबंध में क्या इन्होंने स्वीकृति दे दी है और पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद तब उस का एनाउंसमेंट करना चाहते हैं ? सीधे सीधे इन का उत्तर क्यों नहीं देना चाहते ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the reference made to Jan Hit Nidhi is concerned, I have absolutely no knowledge. If the hon. Member can give me some information, I will be able to find out. (*Interruption*).

SHRI SHEO NARAIN: Where is the Cabinet Minister? He is not present here. You are our guardian in this House; You must protect us.

MR. SPEAKER: I cannot be the guardian for everything. I am only responsible for order in the House. As the guardian, I am unable to control you.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the other aspect of the question referred to by the hon. Member is concerned, as to what the Cabinet has decided on the 20th, the Cabinet has considered two aspects about reorganization of the Board and the reasonable period during which this kind of arrangement can be had. That is for the purpose of giving instructions to the lawyers, what instructions should be given to the laywers representing the Government in respect of the reorganization of the Board and the period during which the new Board can work and also the necessity for giving ample protection.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak): How can he disclose the discussions in the Cabinet?

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi): This hon. Member clearly betrays an animus against the House; he wants the House not to carry information. Thus he is failing in his duty as a representative. This House should have all the information.

MR. SPEAKER: The question asked is very simple. If you think that there is no relevancy or you have no knowledge, you can say that it is not connected with this. But kindly do listen to the categorical questions and the answer should also be categorical.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I very respectfully submit, Sir, with regard to the questions asked, I am at a disadvantage. I cannot travel beyond a certain level because the matter is pending before the court. Whatever I say here should be appreciated within the limits of the doctrine of *sub judice*. That is the difficulty that I have got.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: The court has nothing to do with the cabinet decision.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As I have already submitted and have made a reference in the statement which I read out, the question of reorganisation and also the protection to be given to the employees who had helped during the investigation are the two aspects that were considered and the nature of instructions has to be decided by the Government in relation to that.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल जो थे उनपे तो वह हट गए और दूसरी बातें करने रहे । आप ने तो प्रश्न सुना, कृपा कर के आप तो हमारे हितों की रक्षा कीजिए । आप ने कहा भी उन को कि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर दें लेकिन उन्होंने फिर भी उत्तर नहीं दिया । यह पहले तय कर चुके हैं और पार्लियामेंट सेशन खत्म होने के बाद एनाऊंस करना चाहते हैं, उन के नाम हम लोगों तक को पता हैं लेकिन आज यह कोर्ट का नाम लेकर उसको छिपाना क्यों चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोशिश की है सेटिस्फाई करने की । आप नहीं हो सके या वह नहीं कर सके तो अब मैं यहां बठे बैठे क्या कर सकता हूं ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मिस्टर मोदी और कुमार मंगलम को लेना चाहते हैं, इस का जवाब नहीं दिया ।

MR. SPEAKER: I am on my legs. Mr. Madhu Limaye, are you not asking your question?

श्री मधु लिमये : मैं तो कितनी देर से तैयार हूं । चूंकि उन के प्रश्नों का जवाब नहीं आ रहा था इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ और जब आप खड़े हैं तो मैं कैसे खड़ा होता ?

अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिमंडल के क्या फैसले थे, इस को कहने जा रहे थ लेकिन बीच में चौधरी साहब टपक पड़े और इसलिए वह जवाब मिला नहीं । मैं इन से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर यह अखबारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि उस के ऊपर दो तरह के खतरे हैं, एक खतरा यह है कि पूंजीपतियों के हाथ में यह सारे अखबार हैं और दूसरा खतरा यह कि जब सरकार का प्रभाव बढ़ता है तो हिन्दुस्तान टाइम्स केन्द्रीय सरकार का गजट बन जाता है और टाइम्स आफ इंडिया टाइम्स आफ इन्दिरा बन जाता है, तो इन दोनों खतरों से अगर बचना है तो मैं तीन सवाल इन से पूछना चाहूंगा—सबसे पहले यह सवाल है कि क्या यह बात सही है कि टाइम्स आफ इण्डिया गुट के जो व्यवस्थापक पी०के० राय आदि लोग हैं क्या यह लोग गबन और चार सौ बीस के मुकद्दमें में फंसे हुए हैं और अगर फंसे हुए हैं तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर साधारण कर्मचारी टाइम्स आफ इंडिया का इस तरह के केसेज में फंसेगा तो उसको तो आप मुअत्तल करेंगे लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके खिलाफ आप किसी किस्म की कार्यवाही करने के लिए क्यों तैयार नहीं है । दूसरी बात खुद एम०सी० सीतलवाड साहब ने कहा था इनके बारे में जो चोर हैं उनको चौकीदार न बनाया जाय लेकिन आप लोग इनको चौकीदार बनाते चले जा रहे हैं । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या योजना है यह आपने बिल्कुल नहीं बताई इसलिए क्या मंत्री महोदय इस पर गौर फरमाएंगे कि जो नया बोर्ड बनेगा उसमें आप कम से कम 4 प्रतिनिधि कर्मचारियों को लीजिए दो वर्किंग जर्नलिस्टस के प्रतिनिधि और दो कर्मचारियों के प्रतिनिधि ।

जहां तक चेयरमैन का सवाल है उसको भी आप कर्मचारियों में से लीजिये और साहू जैन को मजबूर कीजिये कि उनके जितने हिस्से हैं, वे सब से पहले जो टाइम्स आफ इंडिया के कर्मचारी हैं, उनको बेचे, उस के बाद इस उद्योग में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता मिले और साधारण जनता को भी शेयर्स दिये जायें । लेकिन दरमियानी अर्से के लिए जैसा आपने कहा है कि साहू जैन के हाथ में नहीं दे सकते हैं । मैं आप से मुत्तफिक हूं लेकिन सरकार के हाथों में भी हम नहीं देना चाहते हैं ।

क्या मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे ? यूरोप में ऐसे कई बड़े अखबार हैं जिनके हिस्सेदार सब कर्मचारी हो गये हैं । मंत्री महोदय मेरी इन दोनों बातों का जबाब दें ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The first question raised by Shri Madhu Limaye is about Shri P. K. Roy and others. P. K. Roy was one of the respondants where others are also involved. Therefore, there is already a case pending against him. He happens to be a defendant in a civil suit filed by the company for recovery of certain sums, I think the

Hon. Member will kindly excuse me if I do not go into further details.

श्री मधु लिमये : मैंने पूछा है कि क्या इनको मुअत्तिल करके रखा है । आज केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों को आपने मुअत्तिल करके रखा है जब कि उनके खिलाफ बहुत मामूली आरोप हैं, लेकिन जो लोग इस कम्पनी में गबन के मामले में फंसे हैं, चार सौ बीसी के मामले में फंसे हैं, उनको क्यों नहीं निकालते हैं, अदालत इसमें कैसे बाधा डालती है समझ में नहीं आता है?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as Shri P. K. Roy is concerned along with this, there are others who are involved in this matter, as respondents or defendants or witnesses. He will kindly excuse me if I do not answer because I do not want to say something that might affect the merits of the case.

श्री मधु लिमये : मजदूरों, कर्मचारियों को हर दिन सस्पेण्ड करते हैं, लेकिन जब बड़े लोगों का सवाल आता है तब ये लोग झुक जाते हैं ।

श्री शिव नारायण : जिन्होंने 19–सितम्बर को स्ट्राइक किया, उनको आपने सस्पेण्ड किया, इनको सस्पेण्ड क्यों नहीं करते हैं ।

If he says about suspension, what is the harm? That will not affect the case. It creates no obstacle in regard to court matters.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: As far as the point raised by Shri Madhu Limaye is concerned, I fully appreciate the force in the suggestion he has made and the logic behind it. This will also be borne in mind when we will have to suggest some names. Several names are being thought about. There is no definite decision taken about the names. Therefore, he may kindly excuse me, if I don't answer anything about names because still the Government have not taken a final view about these matters. Only when a final view is taken, instructions would be given to the counsels appearing on behalf of the Government. We can only give names. It is for the court to pass orders.

श्री मधु लिमये : आप क्या करेंगे ? आप कर्मचारियों के, बैंकिंग जर्नलिस्टस के डायरेक्टर लेंगे या नहीं ? इस बारे में आपकी क्या इच्छा है ?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The suggestion made by Shri Madhu Limaye, I submit, is a very excellent suggesation which would be taken into consideration at the appropriate time.

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have double standards. In case of particular employees you are so harsh. In the case of certain other persons you are so lenient and liberal. Why should all these things continue?

MR. SPEAKER: There is no question of that.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, बनेट कोलमैन का मामला अदालत में है और मंत्री महोदय यहां जो जानकारी इस सदन को देने से इन्कार कर रहे हैं, उस जानकारी को अदालत में आज पेश करने के लिए तैयार हैं ......

श्री मधु लिमये : यह तो सदन का अपमान कन्टेम्पट आफ पार्लियामेन्ट है ।

श्री जार्ज फरनन्डीज : बिल्कुल है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कन्टेम्पट क्या है ?

श्री मधु लिमये : अदालत के सामने देने के लिए तैयार हैं, यहां नहीं हैं—यह तो सीधा कन्टेम्पट आफ पार्लियामेन्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : कन्टेम्पट का कोई सवाल नहीं है ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय इस महीने काबीना की जो मीटिंग हुई, उसमें बनेट कोलमैन कम्पनी के तमाम मामलों के बारे में बहस हुई । काबीना की उस मीटिंग के बाद श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने शान्ति प्रसाद जैन को टेलीफोन किया और यह कहा — जो बात मंत्री अभी यहां कहने के लिए तैयार नहीं है — लेकिन इस बात को शान्ति प्रसाद जैन के वकील ने अदालत में कहा है —ता० 21 को वहां इस मामले पर बहस हुई है कि कल शान्ति प्रसाद जैन के पास फखरूद्दीन अली अहमद का टेलीफोन आया और उन्होंने यह कहा है कि काबीना में फैसला हो गया है जो आपकी दृष्टि से अच्छा हुआ है कि अशोक जैन को जो शान्ति प्रसाद जैन के लड़के हैं उनको चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हैं, बोर्ड में हमारे चार डायरेक्टर रहेंगे और आपके दो डायरेक्टर रहेंगे और अशोक जैन को चेयरमैन बनायेंगे ।

शान्ति प्रसाद जैन के वकील के द्वारा यह बात अदालत में कही गई है जिसको मंत्री महोदय इस सदन में इस समय पेश करने से इन्कार कर रहे हैं । यह सदन का सीधा अपमान है और मधु लिमये ने ठीक कहा है । पिछले आध घंटे से जब से यह बहस चल रही है, यह अपमान तो हो चुका है—इसलिये मैं इस बात का खुलासा चाहूंगा ।

दूसरी बात— मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप टाइम्स आफ इंडिया के मामले में फैसला करना चाहते हैं तो श्री टी०टी० कृष्णमाचारी ने 1964 में शायद यह सुझाव दिया था कि कोई बोर्ड पर कर्मचारियों के दो प्रतिनिधि रहने चाहियें, लेकिन उस समय भी शान्ति प्रसाद जैन तथा अन्य लोगों के दबाव में आ कर अपने इस सुझाव को मानने से इन्कार किया था तो अब जब आप फिर से नया बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो उस समय के लिए हुए निर्णय को अमल में लाने में आपको क्या एतराज है ?

मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट यहां पर दिया है, मैं इस में से दो तीन वाक्य यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

"Certain proposals were received on behalf of the main respondents regarding the reorganisation of the Board of Directors of M/s. Bennet Colemen and Co. Ltd."

मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या सुझाव है? आपके पास क्या सुझाव आये हैं, जिनको आप सर्टेन प्रपोजल्ज कह रहे हैं और जिन पर आप अदालत में बहस करने के लिये तैयार हैं —कृपा कर के इस को साफ करें ।

आपने यह भी कहा है—

"These matters connected with the reorganisation of the board, the period of life of the reorganised board and the protection of the employees who have assisted in the investigations have been considered by Government for making appropriate submissions to the court.".

What are those appropriate submissions that Government are making?

इस का भी यहां पर खुलासा होना चाहिए ।

"In Government's view, the reorganised board should have a majority of nonshareholders directors for a reasonable period in the interests of the company and the employees concerned should be protected."

यह जो नान-आफिशियल डायरेक्टर्स का जिक्र किया गया है—इन का और आपकी सरकार का कितना सम्बन्ध है, कितना रिश्ता है, इस का यहां पर खुलासा होना चाहिये । विशेष कर इस कम्पनी में, कम्पनी ला-एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा 1964 में इसके

लिये जाने से पहले और लिये जाने के बाद जो गलत-व्यवहार करने वाले बड़े अफसर हैं, जिन्होंने दिल्ली के, अहमदाबाद के और बम्बई के कम्पनी के कई अच्छे और इमानदार कर्मचारियों को नौकरी से सस्पेंड कर रखा है, ट्रेड यूनियन में काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से सस्पेंड कर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रान्सफर करने का जो सिलसिला चला है, इन तमाम बातों को लेकर टाइम्ज आफ इण्डिया में जो असन्तोष इस समय है, इस के बारे में आप क्या करने जा रहे हैं ? इन तमाम प्रश्नों का साफ और स्पष्ट उत्तर दीजिये, वर्ना आपका भारी पड़ जाएगा ।

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I would like to dispel one impression which is there. There is nobody as a company law administrator who is running this company. The erstwhile tribunal had appointed a chairman, first Dr. Cooper and when he resigned, Shri D. K. Kunte was appointed as chairman of the company by the Companys Tribunal; the tribunal also appointed certain persons as directors and allowed the option to Government to appoint two directors. That was how the present board of directors came into existence. There is nobody as a company law adminisarator who is running this company. Therefore, I would like to dispel that impression.

13 hrs.

As regards the second question raised by Shri Fernandez, I would very respectfully submit that I have not committed any contempt of the House. They would, I hope, appreciate my difficulty. The matter is pending before the court which is dealing with the merits of the case. Government is only in the nature of a petitioner; it is not an adjudicating authority. It will have to give instructions to counsel depending upon the stage of the case and sometimes even to adjust to circumstances. Suppose the Judge makes a suggestion, that will have to be considered by Government with great respect. Therefore, to go into these details and explain step by step everything that Government would do or propose to do when the matter is pending before the court would be very difficult for me to do on the floor of the House. As circumstances warrant, Government will have to give instructions to the lawyer to present the case.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अशोक जैन के बारे में अपने शांति प्रसाद जैन को कह सकते हैं, सदन को नहीं कह सकते हैं । यह क्या तमाशा है ? (**व्यवधान**)...

श्री एस० एम० जोशी : मैंने भी यह पूछा था क्या सरकारी वकील ने इस चीज को कबूल किया ? (**व्यवधान**)...

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिए कि शांति प्रसाद जैन को 20 तारीख को श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा या नहीं ? .....(**व्यवधान**).....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए । आप में भी थोड़ा सुनने का सब्र होना चाहिए । ..... (**व्यवधान**).....

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I have no knowledge as to whether Shri F. A. Ahmed telephoned Shri S. P. Jain.

श्री मधु लिमये : अपने मंत्री के कामों पर चादर न बिछाइये । .....(**व्यवधान**)

श्री एस० एम० जोशी : जब शांति प्रसाद जैन की तरफ से यह बात कही गई तो सरकारी वकील ने अदालत में इन्कार नहीं किया । .....(**व्यवधान**).....

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अदालत में यह बात कही गई या नहीं ? ...(**व्यवधान**)

श्री शिव नारायण : जो कोर्ट में कहा जाये उसको हाउस में कहने में क्या एतराज हो सकता है ?

श्री मधु लिमये : आप फखरूद्दीन साहब को मत बचाओ । . . . (व्यवधान).

अध्यक्ष महोदय : आप ख्वाम ख्वाह मिनिस्टर को घवरा देते हैं ।

श्री मधु लिमये : यह फखरूद्दीन सहाब को बचाने की साजिश है । . . . (व्यवधान)

SHRI RAGHUNATHA REDDY: There would be a number of proposals being made on each side. Government and counsel, depending upon the nature of the proposals made, will have to consider them.......... (*Interruptions*).

SHRI UMANATH (Pudu Kottai): Shri Shanti Prasad Jain's lawyer has told the court that Government has proposed such and such name in regard to the reorganisation of the broad. Let him confirm or deny it.

MR. SPEAKER: He has specifically said in the House that Shanti Prasad Jain's counsel had put these two points in the Court. Of course, if it was true, they should have been known or would have been reported. When this has been conveyed to the court, what is left of the secrecy?

SHRI MADHU LIMAYE: Do not try to save Fakhruddin! Speak with God as your witness.

SHRI M. L. SONDHI: May I say that truth makes a man fearless? If truth is on his side, he need not fear anybody.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The Counsel representing Shanti Prasad Jain might have said...... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: You may look and say if you are aware of it or not. There is no question of 'might have . . .'.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I can only give information in respect of suggestions made by the Government Counsel...... (*Interruptions.*)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आज सरकार इस बात पर अदालत में जवाब देने जा रही है । ये क्या बोल रहे हैं ? . . (व्यवधान) . .

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अभी मेरे मित्र, जार्ज फरनेन्डीज ने मंत्री महोदय से कहा कि आया शांति प्रसाद जैन के वकील ने यह बयान कोर्ट में दिया है या नहीं कि फखरूद्दीन अली साहब ने उनको टेलीफोन किया और यह वायदा किया कि उनका लड़का मेनेजिंग डायरेक्टर बनाया जायेगा . . . (व्यवधान) . . . . तो मेरा कहना यह है कि आज यह सरकार जवाब देने जा रही है इस बात का कि आया वह चीज ठीक है या नहीं, तो जब सरकार अदालत में यह जवाब देने जा रही है और अदालत में शांति प्रसाद जैन के वकील ने बयान दिया है तो आप उसको यहां पर क्यों नहीं बताना चाहते हैं ? . . . . . . (व्यवधान) . . . . . .

SHRI RANGA: He should be frank. It seems there is something fishy and they are trying to hide it.

श्री मधु लिमये : हां नहीं कहना चाहिए हाउस की सम्मति के बिना . . (व्यवधान) . .

श्री कंवरलाल गुप्त : ये कांसपिरेसी पर पर्दा डालना चाहते हैं ।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । व्यवस्था का प्रश्न इसलिए उठता है कि बार बार पूछने पर भी ये जानकारी नहीं दे रहे हैं । प्रश्न जानकारी हासिल करने के लिए पूछे जाते हैं—यह नियम 41 में लिखा हुआ है । यहां पर यह जानकारी मांगी गई कि

क्या शांति प्रसाद जैन के वकील ने यह कहा और उसके ऊपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है । आज सरकार हां कहने जा रही है और सदन को पता ही नहीं चलेगा तो मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि सदन की सम्मति लिये बिना शांति प्रसाद जैन के किसी भी प्रस्ताव पर आपको हां नहीं कहनी चाहिए ।

MR. SPEAKER: It is a simple question. They want to know if you are aware of it or not.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: I shall have to find out the information from the Government Counsel and then only give the information that is asked. Before that I cannot say.

SHRI M. L. SONDHI: His reputation will suffer if he does not say the truth. We are in no hurry for lunch. Democracy, Press and human rights demand of him a proper answer. What is wrong? He is a young man. Procrastination is evil and he should shun it.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): He can make a statement later. Let him ascertain it. The House is sitting till 6 O'clock.

MR. SPEAKER: I would like to ask the Minister that he should give a categorical reply: whether he is aware of it or not. That is all.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M. R. KRISHNA): He said he is not aware.

श्री शिव नारायण : आप के हुक्म को नहीं मान रहे हैं ।

श्री लखन लाल कपूर (किशनगंज) : पूंजीपतियों के साथ सरकार कांमप्रेंसी कर रही है । यह अच्छी बात नहीं है ।

MR. SPEAKER: Are you aware of it or not?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The question raised is whether a particular type of submission has been made by the council of Shri Shanti Prasad Jain to the court. That is the question. I will have to verify and then answer. (*Interruption*).

SHRI UMANATH: That is not the question.

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

SHRI UMANATH: The question is this. S. P. Jain's lawyer had made a submision in the name of the Government. The question is whether Government had made such suggestions as claimed by him. He can say he is not aware of any such suggestion having been made or he can say that he wants notice of the question. That is the reply we want. It is not the other thing.

MR. SPEAKER: If the Minister has not heard it, why should he involve himself like this? If he is not aware of it, he may say he is not aware of it.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: When I said I will have to verify that does not mean that I am not at all aware of it, but I will have to verify. (*Interruption*)

13.11 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

KEROSENE (FIXATION OF CAILING PRICES) FOURTH AMENDMENT ORDER, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN): I beg to lay on the Table a copy of the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Fourth Amendment Order, 1969, published in Notification No. G.S.R. 1838 in Gazette of India dated the 1st August, 1969, under sub-section (6) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955. [*Placed in Library. See* No. LT-1800/69.]